LOK SABHA DEBATES

1 | 2

Vol. L *First day of the Thirteenth Session of Second Lok Sabha* *No* 1

LOK SABHA

Tuesday, February 14, 1961/*Magha* 25, 1882 (*Saka*).

The Lok Sabha met at Fifteen minutes past Twelve of the Clock.

12.15 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBER SWORN

Shri Rajendra Pratap Singh (Rae Bareli)

12.15¼ hrs.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker: I have to inform the House of the sad demise of two of our friends, namely Shri C. R. Iyyunni and Sri Krishna Sinha.

Shri Iyyunni was a Member of the First Lok Sabha during the years 1952—57. He passed away on the 21st January, 1961 at Trichur at the age of 71.

Dr. Sri Krishna Sinha was a Member of the former Central Legislative Assembly during the years 1935—37 and of the Constituent Assembly during the years 1946—49. He was the Chief Minister of Bihar at the time of his death. He passed away at Patna on the 31st January, 1961 at the age of 74.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved families.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a minute.

12·16½ hrs.

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 14th February, 1961.

Presidents' Address

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण,

संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं।

2. पिछला वर्ष हमारे लिये आन्तरिक और बाहरी दबाव व कठिनाइयों का वर्ष रहा है। मेरी सरकार ने अपनी आधारभूत नीति के सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते हुए और भविष्य में विश्वास रखते हुए बड़े परिश्रम के साथ सब समस्याओं का सामना किया है। यद्यपि अभी बहुत सी जटिल समस्याओं का सुलझाया जाना बाकी रहता है अथवा उनका समाधान हो रहा है, देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जिन से सफलता की कुछ आशा बंधती है।

3. हमारे राष्ट्र की सर्वाधिकार-सम्पन्न भूमि पर आक्रमण तथा हमारी सीमा के

[राष्ट्रपति]

अतिक्रमण की समस्यायें अभी नहीं सुलझ पाईं, किन्तु मेरी सरकार उन समस्याओं तथा उन से सम्बन्धित समस्त उलझनों के प्रति जागरूक है। रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की ओर वह निरन्तर ध्यान दे रहा है और साथ ही संचार के साधनों द्वारा सम्पर्क स्थापित करके उन स्थानों का विकास कर रही है।

4. लांगजू में चीन ने जो सैनिक चौकी स्थापित की थी, यद्यपि उसे उसने वहां से हटा लिया है और भारतीय क्षेत्र का और अधिक उल्लंघन करने की चेष्टा उसने नहीं की है, किन्तु तो भी उसका दुराग्रह जारी है। हमारी सीमा के उस पार हमारे प्रति जो वैर-भाव जारी है उसे ध्यान में रखते हुये मेरी रकार प्रतिरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में निरन्तर प्रयत्नशील है। फिर भी मेरी सरकार उन सिद्धान्तों पर दृढ़ रहेगी जिन्हें हमारा देश दूसरे देशों के साथ अपने सम्बन्धों के लिय आधारभूत मानता है। मेरी सरकार चीन के एकतरफा निर्णयों अथवा कार्रवाई के परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकती।

5. इस शान्तिपूर्ण किन्तु दृढ़ नीति और रक्षा की तैयारी को जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, हमारे लोगों का समर्थन प्राप्त है और इस का विश्व-मत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हमारा यह दृढ़ मत है कि भारत और चीन के बीच की सीमायें चिर-काल से संधियों, रीति-रिवाजों तथा व्यवहार द्वारा भली प्रकार निश्चित रही हैं। मेरी सरकार को आशा है कि चीन वर्तमान अनिच्छा अथवा दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही उन सीमाओं के बारे में, जो हमारे और उसके बीच सांझी हैं, हमारे देश के साथ संतोषजनक समझौता करने के लिए तैयार हो जायेगा। अपने महान् पड़ोसी के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, जिन्हें उन्नत करने के लिय मेरी सरकार सदा उत्सुक रही है, तभी एसी वास्तविकता का रूप धारण कर सकते हैं जो स्थिर रहे और जिससे हम दोनों देशों की भलाई हो और एशिया तथा विश्व की स्थिति में स्थिरता आय।

6. मेरे प्रधान मंत्री और चीन के प्रधान मंत्री के बीच नई दिल्ली में गत अप्रैल, में किए गए और बातचीत के अन्त में संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा घोषित हुए समझौते के अनुसार, दोनों देशों की सरकारों द्वारा मनोनीत अधिकारी नई दिल्ली, पेकिंग और रंगून में बातचीत करते रहे हैं। यह बातचीत अब समाप्त हो चुकी है। मेरी सरकार को अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है वह संसद् के सामने रखी जाएगी।

7. अफ्रीकी भूखंड में बहुत से देशों का स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में उदय और संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्ण सदस्यों के रूप में उनके प्रवेश का मेरी सरकार स्वागत करती है। अफ्रीका में जागृति की लहर और कई सर्वाधिकार सम्पन्न गणराज्यों का उदय हमारे लिए हर्ष का विषय है। इन राष्ट्रों द्वारा तटस्थ रहने और शीत युद्ध के संघर्ष से अलग रहने की घोषणा का हम खास तौर से स्वागत करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में मेरी सरकार ने जिस नीति का बराबर अनुसरण किया है, यह घोषणा, वास्तविकता के आधार पर, उस नीति का निष्पक्ष समर्थन है।

8. कांगो की स्थिति से मेरी सरकार बराबर चिन्तित है। हाल में आज़ाद हुए इस देश की स्वतन्त्रता और एकता, अफ़्रीकी भूखंड की उन्नति और विकास, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की क्षमता तथा प्रतिष्ठा और दुर्बल राष्ट्रों की शक्तिशाली राष्ट्रों के आक्रमण से सुरक्षा, इन सब प्रश्नों का कांगो की स्थिति से सम्बन्ध है। बेल्जियम के शस्त्रास्त्र और उसके सैनिक

और अर्द्धसैनिक नागरिकों का दबाव और संयुक्त राष्ट्र के निश्चित निर्णयों के विरोध में कांगो में कुछ प्रतिस्पर्धी दलों को बल्जियम द्वारा सहायता, कांगो की स्थिति में उलझनों के यही प्रमुख कारण हैं ।

9. मेरी सरकार बराबर उस नीति का अनुसरण करती रहेगी जिसका आधार संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में हमारी आस्था और कांगो के लोगों को उनकी नवोदित स्वाधीनता भोगते हुए देखने की हमारी उत्कट इच्छा है । इस उद्देश्य से मेरी सरकार बल्जियनों के हटाए जाने और राजनीतिज्ञों की, विशेष कर उनकी जिन्हें संसदीय अधिकार प्राप्त हैं, कारावास मे रिहाई, परस्पर-विरोधी और सशस्त्र दलों के तटस्थीकरण, वहां की पार्लेमेंट के संयोजन और संवैधानिक सत्ता के पुनःस्थापन पर बराबर जोर देती रही है ।

10. इधर हमारे देश के निकट लाओस में भी स्थिति ऐसी बन गई है जिससे भारी चिन्ता होने लगी है । इस स्थिति में और अधिक बिगाड़ न होने पावे, इस दृष्टि से, मेरी सरकार संबद्ध राष्ट्रों की सहमति से अन्तर्राष्ट्रीय कमिशन को फिर से कार्यान्वित करने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रही है । वहां संघर्ष स विस्तार के, एशिया और समस्त विश्व मे, भीषण परिणाम हो सकते हैं और ऐसी घटना की रोक-थाम करने की मेरी सरकार की नीति है ।

11. गोआ अभी भी पुर्तगाल के उपनिवेशवादी अधिकार में है । मेरी सरकार भारत के इस भ ग की जहां अभी भी जीर्ण उपनिवेशवाद का बोलबाला है, शांतिपूर्ण अज़ादी के लिये वचनबद्ध है ।

१२. भारत के पड़ोसी राज्यों और अन्य देशों के साथ हमारे शांतिपूर्ण सम्बन्ध बराबर बने हैं । मेरी सरकार अपनी शांति पूर्ण सह-अस्तित्व और पड़ोसी सद्भाव की नीति पर दृढ़ करते हुय किसी भी देश के साथ सैनिक-सन्धियों में उलझे बिना इन संबन्धों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है ।

१३. सद्भावना बढ़ाने के हेतु दूसरे देशों के साथ यात्राओं का विनिमय किया गया । सोवियत संघ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के प्रत्युत्तर में मैंने रूस की यात्रा की । वहां के राष्ट्रपति, उनकी सरकार और वहां की जनता ने जो मेरा हार्दिक स्वागत किया उसके लिये मैं आभारी हूं । हमारे उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेटस और फ्रांस की यात्रायें कीं ।

१४. हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त अरब गणराज्य, लेबनान, टर्की और पाकिस्तान की यात्राएं कीं । अन्य मंत्रीगण और भारत सरकार के कुछ विशेष प्रतिनिधि मंडल आपसी सद्भावना बढ़ाने के लिये अथवा विशेष उद्देश्य को ले कर विविध देशों की यात्रा पर गए । इन देशों में सिलोन, मेक्सिको, पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के देश, इथिओपिया, नाइजीरिया घाना और मंगोलिया लोक गणराज्य शामिल हैं ।

15. गत वर्ष उरुगवे, पेरागवे, कांगो मलागासी गणराज्यों के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुये ।

16. मेरी सरकार ने एक स्वाधीन गणतंत्र राज्य के रूप में साइप्रस के उदय का जहां एक दीर्घकालीन उपनिवेशवादी सत्ता का अन्त हुआ, स्वागत किया है ।

17. महिष्मती महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय और एडिनबरा के ड्यूक राजकुलमान्य प्रिंस फिलिप ने भारत आने के लिये मेरे निमंत्रण को कृपापूर्वक स्वीकार किया । उन्हें अपने बीच पा कर हमें खुशी होती है और वे मेरे ही नहीं, मेरी सरकार और हमारी जनता के भी सम्मानित अतिथि हैं ।

18. हमें जापान के सम्राट के प्रतिनिधित्व-रूप आये हुए राजकुलमान्य राज-

[राष्ट्रपति]

कुमार और राजकुमारी, रूस के प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव, नेपाल के महामहिम सम्राट, संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्णो, गिनी के राष्ट्रपति सकू तूर, जर्मन संघीय गणतंत्र के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर थ्योडोर रस, फिलीपीन्स के उपराष्ट्रपति मकापगल और चीन, बर्मा, पोलैंड, नेपाल तथा सिलोन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत करके बड़ी खुशी हुई। भूटान और सिक्किम के महामहिम महाराजा का अपने सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। इन सब विशेष सम्माननीय मेहमानों की भारत यात्रा हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।

19. आज संसार के सामने सबसे प्रमुख बात निःशस्त्रीकरण की है। हर अवसर पर, विशेष कर संयुक्त राष्ट्र संघ में, इस विषय में राष्ट्रों के बीच, खास कर बड़ी शक्तियों के बीच, समझौते के लिए आधार के निर्माण में मेरी सरकार प्रयत्नशील रही है। इसके लिये मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण परिषद् में कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि निःशस्त्रीकरण की बातचीत का निश्चित आधार यह होना चाहिये कि देशों के बीच आपसी झगड़ों के निपटारे के लिये युद्ध को साधन न माना जाय और उसे गैर-कानूनी करार दिया जाय।

20. हमें खेद है कि हमारी कोशिशों के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की सरकार मूल भारतीय नागरिकों के विरुद्ध भेद-भाव करने और जातीय भेद-भाव के आधार पर अपने समाज का संगठन करने में लगी है। मानवीय गौरव की अवहेलना, मानव के अधिकारों के उल्लंघन और पृथक्करण की इस नीति के अनुसरण से समस्त संसार को गहरा धक्का लगा है।

21. राज्यों की सरकारों के सहयोग से योजना आयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है और यह रूप रेखा सिद्धान्त रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। जैसे ही रिपोर्ट का प्रारूप तैयार होगा उसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने और उसके बाद संसद् के सामने रखा जायगा।

22. 1952–53 के मूल्यों के आधार पर अनुमान है कि 1959–60 की राष्ट्रीय आय 12,212 करोड़ होगी, जबकि 1955–56 में यह आय 10,920 करोड़ थी। आय में वार्षिक वृद्धि इतनी रफ्तार से नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे। 1957–58 और 1959–60 में खेती को जो भारी नुकसान पहुंचा, वही इसका कारण था। हमें आशा है इस साल की फसलें अच्छी हैं और औद्योगिक उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा रहा है।

23. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूल्यों के स्तर करीब 6 प्रतिशत ऊपर गये हैं। इसे रोकने के लिये सरकार ने जो उपाय अपनाये हैं, उनसे कुछ रोकथाम हुई है और कहीं कहीं, जैसे कपड़े के मामले में, सरकारी कार्यवाही के कारण मूल्यों में कमी होने लगी है। विदेशी मुद्रा के संचय में कमी के कारण हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद खेती और उद्योग दोनों की स्थिति आशाजनक है।

24. पंचायती राज अथवा ग्राम लोकतन्त्र ने तीव्र गति से प्रगति की है। मेरी सरकार को आशा है कि 1961 के समाप्त होने से पहले पंचायती राज सम्बन्धी संस्थायें सभी राज्यों में स्थापित हो चुकेंगी। इन संस्थाओं के मुताबिक

संचालन और सहायता के लिये गैर-सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग का विस्तृत कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। सर्विस सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या में लगभग 1 करोड़ 80 लाख की वृद्धि हुई है। आशा है ये समितियां 190 करोड़ रुपये तक लोगों को ऋण के रूप में दे सकेंगी।

25. 1960–61 में फिर कृषि-उत्पादन में निश्चित उन्नति हुई है। अन्दाजा है कि 1960–61 की खरीफ फसल में अनाज का उत्पादन पहले वर्ष की अपेक्षा 20 लाख टन अधिक होगा। आशा है यह 1958-59 की अपेक्षा भी अधिक होगा। उस वर्ष का उत्पादन अधिकतम था। रबी की फसल की स्थिति भी आशाजनक है। सब मिलाकर, आशा है कृषि-उत्पादन की दृष्टि से 1961 हमारे बहुत अनुकूल पड़ेगा। देश में उत्पादन में वृद्धि के कारण और मेरी सरकार ने गल्ला संचित करने की दिशा में जो ठोस कदम उठाये हैं उनके फल-स्वरूप, अनाज के भाव पहले ही गिरने शुरू हो गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार सिंचाई की छोटी योजनाओं और बीज-उत्पादन के लिए फार्मों की स्थापना के कार्यक्रम पर जल्द ही पूरी तरह अमल होने की आशा है। भरपूर जुताई को देश भर म और कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खेती के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है जिससे कि राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार दृढ़ हो सके। हमारा लक्ष्य अनाज के मामले में आत्मभरित होना और दूसरे कृषि-उत्पादनों को यथोचित प्रोत्साहन देना है।

26. किन्हीं दिशाओं में औद्योगिक उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा है। 1960 के पहले दस महीनों में उत्पादन की सूची 167 थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में वह 149 थी। सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले तीन इस्पात के कारखाने लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। औद्योगिक मशीनरी और मशीनी औजारों के निर्माण में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। खनिज तेल के नये साधनों का पता लगा है, खासकर गुजरात में अंकलेश्वर में और आसाम में सिबसागर में। आशा है कि परीक्षण के रूप में तेल का उत्पादन इस वर्ष शुरू हो जायगा। तेल साफ करने के दो कारखानों पर काम चालू है और तीसरा कारखाना स्थापित होने जा रहा है।

27. कनाडा-भारत रीएक्टर जो हाल ही में चालू हुआ है, हमारा तीसरा रिएक्टर है। इसके उद्घाटन से उद्योगों, चिकित्सा और खेती सम्बन्धी कामों में अणुशक्ति के उपयोग की संभावना बढ़ी है।

28. बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं में चम्बल नदी योजना, गांधी सागर बांध और कोटा बराज का उद्घाटन हो चुका है और भाखड़ा में 90 हजार किलोवाट बिजली की 5 इकाइयों में से दो खोली जा चुकी हैं। बाकी तीन भी आगामी कुछ महीनों में ही खुल सकेंगी, इस बात की पूरी सम्भावना है।

29. सरकारी कर्मचारियों की हाल में होने वाली खेदजनक हड़ताल को छोड़कर, कामगर सम्बन्धों में सुधार हुआ है। अनुशासन नियमावली के लागू करने का अच्छा असर पड़ा है और नागे के दिनों की संख्या में काफी कमी हुई है। सरकारी मजदूर बीमा योजना का विस्तार कर उसके अन्तर्गत 15.8 लाख और कामगरों को शामिल कर लिया गया है। सूती कपड़ा, सीमेन्ट और चीनी जैसे

[राष्ट्रपति]

प्रमुख उद्योगों की देखभाल त्रिदलीय वेज बोर्ड पहले ही कर चुका है और अब जूट उद्योग और चाय के बगीचों के लिए ऐसे बोर्डों की नियुक्ति कर दी गई है। कुछ औद्योगिक इकाइयों में प्रबन्धकार्य में मजदूरों की शमूलियत की प्रयोगात्मक योजना लागू की गई है।

30. प्रशासन में हिन्दी को स्थान देने की दिशा में उन्नति हुई है। हिन्दी के विकास और प्रचार के सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों को कार्य रूप देने के लिये एक केन्द्रीय हिन्दी विभाग की स्थापना की गई है।

31. जैसा कि संसद् सदस्य जानते हैं, गत जुलाई में नागा नेताओं से बातचीत के फलस्वरूप मेरी सरकार ने भारतीय संघ के अन्तर्गत नागालैण्ड नामक पृथक राज्य के गठन का निश्चय किया था। इस दिशा में पहले कदम के रूप में मैंने एक अधिनियम जारी किया है, जिसके अनुसार संक्रान्ति काल की अवधि में नागालैण्ड के प्रशासन में राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिये प्रतिनिधियों की अन्तरिम परिषद निर्वाचित की गई है। मेरी सरकार उन विरोधी तत्वों को दबाने के लिए कृतसंकल्प है जो वहां के लोगों के लिए कठिनाइयां और कष्ट पैदा कर रहे हैं।

32. 1961–62 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े यथापूर्व आपके सामने रखे जायेंगे।

33. संसद् के पिछले सत्र के बाद दो अधिनियम, "दी यू० पी० शुगरकेन सेस (वेलिडेशन) आर्डिनेन्स" और "दी बैंकिंग कम्पनीज (अमेण्डमैन्ट) आर्डिनेन्स" जारी किए गए हैं।

34. संसद् के सदस्यगण, गत वर्ष जब मैंने आपके समक्ष भाषण दिया था उस समय से आपके दोनों सदनों ने 67 विधेयक पारित किए हैं। 16 विधेयक पिछले सत्र से आपके सामने विचाराधीन है। उन्हें पारित करने की दिशा में मेरी सरकार इस सत्र में कदम उठायेगी।

35. दहेज उन्मूलन विधेयक पर दोनों सदनों में कुछ मतभेद है। इस विधेयक पर विचार करने के लिये मेरी सरकार संसद् का संयुक्त सत्र बुलाने की दिशा में उचित कार्यवाही करेगी।

36. मेरी सरकार अन्य विधेयकों के अतिरिक्त निम्न विधेयक आपके विचाराधीन प्रस्तुत करेगी——

1. दी इन्कम-टेक्स (अमेण्डमेंट) बिल।
2. दी एक्सट्राडीशन बिल।
3. दी इण्डियन पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइन्स बिल।
4. दी इसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल।
5. दी शुगर एक्सपोर्ट प्रोमोशन (अमेंडमेंट) बिल।
6. दी नारकोटिक्स बिल।
7. दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बिल।
8. दी हिमाचल प्रदेश एबोलिशन आफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एन्ड लैण्ड रिफार्म्स (अमेंडमेंट) बिल।

37. संसद् के सदस्यगण, मैंने गत वर्ष की प्रमुख घटनाओं और सफलताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। आगामी वर्ष में अपनी सरकार के कार्यक्रम की तरफ भी मैंने आपका ध्यान खींचा है।

हम सब के सामने जो महान कार्य और जिम्मेदारियां हैं उनकी ओर भी मैंने संकेत किया है। मुझे इसमें संदेह नहीं कि इन सब कामों पर आप ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे आर्थिक आयोजन, हमारी प्रतिरक्षा, विश्वशान्ति और पर धोन राष्ट्रों की संघर्ष सम्बन्धी बहुत सी समस्याओं को सुलझाने के लिये और हमारे देशवासियों को आश्वस्त करने के लिये मेरी सरकार को आपका विवेक, सतर्कता और सहयोग उपलब्ध होगा। हमारे देश के साधन और राष्ट्र के लोगों की योग्यता, प्रगति तथा राष्ट्रीय पुर्नानिमाण के उन ऐतिहासिक और महान् कामों में संलग्न हैं, जिनका दायित्व हम पर आता है।

38. मेरी सरकार बराबर ऐसी एक योजना को चलाने और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती रहेगी जिससे कि उसके नीति सम्बन्धी निर्णयों के निर्माण और उनपर अमल के बीच कम से कम समय लगे। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे प्रजातन्त्र में और उसके विकासोन्मुख महान आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम में प्रत्येक स्तर पर जनसाधारण भाग ले सकें। यदि हमें एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में गौरव और सफल प्रयत्न की भावना के साथ जीवित रहना है तो यह हमारे लिये आवश्यक है। राष्ट्र की समस्त जनता के सामाजिक कल्याण की एकसूत्रता, जनतात्मक और समाजवादमूलक समाज के संगठन की ओर ऐसी प्रगति जिसमें परिवर्तन सामयिक हो और उन्नति आत्म-चालित हो—हमारा लक्ष्य है, जिसको हमें शान्तिपूर्वक और लोगों की सहमति से प्राप्त करना है।

39. संसद् के सदस्यगण, अब मैं आपको नये सत्र का काम सौंपता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सन्मति, सहिष्णुता, और सामूहिक प्रयत्न की भावना आपका पथ-प्रदर्शन करेगी। आपके प्रयत्न पूर्ण सफल हों, और हमारे देश तथा उसके जनगण और विश्व के लिए, जिनकी सेवा के लिये हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, यही मेरी कामना है।

The President: Members of Parliament, I welcome you to your labours in a new session of Parliament.

2. The year we have left behind has been one of considerable stress and strain both internally and externally. My Government have faced the problems that arose by their strenuous endeavours and by firm adherence to the principles of their basic policy, and with confidence in the future. Though many and stubborn problems still await solution, or are in the process of being solved, the situation both at home and abroad shows signs of improvement and justifies hope and cautious optimism.

3. The problems of aggression on and incursions into the sovereign territory of the Union have yet to be resolved, but my Government is well alert to them and to all their implications. Defensive arrangements, including the opening up of areas by better communications and development, receive their continuous and careful attention.

4. While China has withdrawn from the military post it had established at Longju and not attempted any further violations of Union territory, her intransigence continues. It is the constant endeavour of my Government to maintain our defensive strength in the face of this continuing hostility from across our frontier. My Government will however, seek to adhere firmly to the principles which this Nation regards as basic in our relations with nations. They cannot accept the results of unilateral action or decisions taken by China.

[The President.]

5. This peaceful but firm policy and progressive preparedness for defence has the support of our people and has also profoundly influenced world opinion. We firmly hold that the frontiers between India and China have been for long well established by treaties, custom and usage. In spite of present unwillingness, or even intransigence, my Government hope that, sooner rather than later, China will persuade herself to come to a satisfactory agreement with our country in regard to our common frontiers. Friendly relations with our great neighbour, which my Government have always sought to promote, can then become a reality which will endure and contribute to our common good and to stability in Asia and the world.

6. In pursuance of the agreement announced in the joint communique, issued in April last at the end of the meeting in Delhi between the Prime Minister of China and my Prime Minister, designated officials from their respective Governments have been engaged in talks in New Delhi, Peking and Rangoon. These talks have now concluded. The report submitted to my Government by their officials will be laid before Parliament.

7. My Government have welcomed the emergence of many independent countries in the continent of Africa to full statehood and their admission as full members in the United Nations. This awakening of Africa and the emergence of many sovereign republics is a matter of gratification to us. We welcome especially their declarations to remain unaligned and not to become involved in the cold war conflict. This constitutes a welcome vindication, on merits, of the policy consistently followed by my Government in regard to international relations.

8. The situation in the Congo continues to cause my Government deep concern, involving as it does the freedom and integrity of this recently liberated country, the progress and development of the African continent itself, as well as both the prestige and potency of the United Nations as an instrument for settling international problems and the protection of the weak against aggressive countries. The pressure of Belgian arms, military and semi-military personnel, and their aid to some of the rival groups in the Congo, in defiance of reiterated decisions of the United Nations, are the main disturbing factors in the Congo situation.

9. My Government will continue to follow a policy based upon their dedication to the purposes of the United Nations and their desire to see the Congolese people in the full enjoyment of their newly won freedom. To this end, my Government have consistently urged the withdrawal of the Belgians, the release of political personalities and more particularly those who have parliamentary immunities, the neutralization of factional forces and armed groups, and the summoning of Parliament and the restoration of constitutional authority.

10. Nearer our own country, in Laos also, a situation has developed that causes grave concern. My Government continue to use their best endeavours for the reactivation of the international Commission with the consent and authority of all concerned, to prevent further deterioration of the situation. Spread of conflict there might have serious repercussions in Asia and the world, and it is the policy of my Government to endeavour to avert it.

11. Goa continues to be under the colonial domination of Portugal. My Government stand committed to the peaceful liberation of this part of India where a decadent colonialism still survives.

12. India's relations with her neighbours and other countries have continued to be peaceful. My Government, firmly adhering to the policy of peaceful co-existence and good neighbourliness, seek to promote these relations without becoming entangled in military alliances with one country or another.

13. To promote goodwill, there have been exchanges of visits with other countries. I visited the Soviet Union to return the courtesy of the visit of the President of the Union of Soviet Socialist Republics to India. I am grateful for the warm welcome which the President, his Government and the people of his country extended to me. The Vice-President visited the United States of America and France.

14. My Prime Minister paid visits to the United Arab Republic, Lebanon, Turkey and Pakistan. Other Ministers and some special representatives of Government have visited various countries either on missions of goodwill or for definite purposes. These countries include Ceylon, Mexico, the countries of Western and Eastern Europe, Ethiopia, Nigeria, Ghana and the Mongolian People's Republic.

15. Diplomatic representation was established last year with the Republics of Uruguay, Paraguay, the Congo and the Malagasy Republic.

16. My Government welcomed the emergence of Cyprus as an independent Republic, thus terminating the long period of colonial domination.

17. Her Majesty Queen Elizabeth II and His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh, kindly accepted my invitation to visit India. We have been happy to have them with us, and they are the honoured and welcome guests not only of myself, but of my Government and our people.

18. We have also had the privilege of welcoming to our country Their Imperial Highnesses the Crown Prince and Princess of Japan, representing His Imperial Majesty the Emperor of Japan, Mr. Khrushchev, Prime Minister of the Soviet Union, His Majesty the King of Nepal, President Nasser of the United Arab Republic, President Soekarno of Indonesia, President Sekou Toure of Guinea, Professor Theodore Heuss, former President of the Federal Republic of Germany, Vice-President Macapagal of the Philippines, and the Prime Ministers of China, Burma, Poland Nepal and Ceylon. We are also happy to receive Their Highnesses the Maharajas of Bhutan and Sikkim as our distinguished guests. The visits of all these high dignitaries have been a great honour to us.

19. The main issue before the world today is that of disarmament. My Government have persevered on every occasion, more particularly in the United Nations, to assist to formulate a basis of agreement among nations, more especially among the Great Powers, in this regard. To this end, my Government have placed proposals before the General Assembly of the United Nations, the purpose of which is that disarmament negotiations should be definitely directed to the outlawing of war as an instrument for settling disputes between countries.

20. The Union of South Africa persists, much to our regret and in spite of every effort that we make, to discriminate against her nationals of Indian origin and to build her society on the basis of total racial discrimination, that is, apartheid. The disregard of human dignity, the violation of human rights and the policy and practice of apartheid have shocked the world more than ever before.

21. The outline of the Third Five Year Plan has been completed by the Planning Commission with the co-operation of the State Governments and has been approved in principle by the National Development Council.

[The President.]

As soon as the Draft Report is ready, it will be placed again before the National Development Council, and later before Parliament.

22. The national income for 1959-60 is estimated to be Rs. 12,210 crores at 1952-53 prices, as compared with Rs. 10,920 crores in 1955-56. The annual rate of increase has not been as much as we had hoped. This was due to severe setbacks suffered by agriculture in 1957-58 and 1959-60 This year's crops, however, are expected to be good, and industrial production is rapidly rising.

23. Price levels have registered a rise of about 6 per cent. as compared to the previous year. Various measures that my Government have taken have checked this rise and, in some cases, such as cloth, prices have shown a downward movement because of Government action. In spite of the difficulties encountered and the decline in our foreign exchange reserves, the outlook, both in agriculture and industry, is definitely promising.

24. Panchayati Raj, or village democracy, has made rapid strides. My Government hope that before the end of 1961, Panchayati Raj institutions would have been introduced in all the States. An elaborate programme for the training of non-officials to help these institutions efficiently, has been inaugurated. Service Co-operatives have increased their membership by approximately 18 million and are expected to disburse loans to the extent of 190 crores of rupees.

25. Agricultural production has again shown definite improvement in 1960-61. The production of Kharif cereals in 1960-61 is now estimated to be more than two million tons higher than that in 1959-60, and it is expected to be higher than even in 1958-59 when our production figure was the highest on record. The prospects of the Rabi crop are also bright. On the whole, 1960-61 may turn out to be a very good year from the point of view of agricultural production. The increase in internal production, along with the measures taken by my Government to build up substantial reserve stocks, has already brought about a healthy trend in foodgrain prices. The targets of minor irrigation and seed multiplication farms, laid down in the Second Five Year Plan, are expected to be realised almost fully. Intensive cultivation is being encouraged throughout the country, and, more especially, in selected areas. Under the Third Five Year Plan, agricultural development is being given a high priority, so as to provide a strong base for the economic development of the country. The aim is to achieve self-sufficiency in foodgrains, and to increase considerably other forms of agricultural production.

26. Industrial output has risen, in some cases, spectacularly. For the first ten months of 1960, the production index was 167 as against 149 for the corresponding period of the previous year. The three steel plants in the public sector have been almost completed and are now in progressive production. The manufacture of industrial machinery and machine tools has made satisfactory progress. New sources of oil have been discovered, notably in Ankleshwar in Gujerat and in Sibsagar in Assam. It is expected that trial production will commence this year. Work on two refineries is proceeding, and a third refinery is also going to be established.

27. The prospects of the use of atomic energy for industrial purposes, as well as for medical and agricultural uses, have advanced by the inauguration of the third reactor, the Canada-Indian reactor, which came into operation recently.

28. Among multi-purpose river valley projects, the Chambal River Project, the Gandhi Sagar Dam and the Kotah Barrage were inaugurated, and two of the five units of 90,000 kilowatts each have been commissioned at Bhakra. The remaining three units are likely to be commissioned in the course of the next few months.

29. Labour relations, apart from the recent regrettable strike by Government employees, have improved. The Code of Discipline has exercised a healthy influence, and there is an appreciable fall in the number of days lost. The Employees' State Insurance Scheme has been extended to further areas to cover about 15·8 lakh factory workers. Tripartite wage boards have already dealt with major industries of cotton textiles, cement and sugar and have been set up for jute and tea plantations. Pilot schemes for workers' participation in management have been introduced in some industrial units.

30. Progress has been made in regard to the introduction of Hindi in the administration. A Central Hindi Directorate has been constituted to carry out the decisions of Government regarding the development and propagation of Hindi.

31. As Members of Parliament are aware, in July last my Government decided in consultation with the Naga leaders to constitute a separate State of Nagaland within the Indian Union. As a first step, I have promulgated a Regulation under which representatives have been elected to an Interim Body to assist and advise the Governor in the administration of Nagaland during the transitional period. My Government are determined to put down the hostile elements which are creating so much hardship and suffering for the people there.

32. A statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the financial year 1961-62 will, as usual, be laid before you.

33. Two Ordinances, namely, "The U.P. Sugarcane Cess (Validation) Ordinance" and "The Banking Companies (Amendment) Ordinance", have been promulgated since the last Session of Parliament.

34. Members of Parliament, since I addressed you last, your two Houses have passed 67 Bills. There are 16 Bills pending before you from the last session. My Government will take steps to seek the passage of these Bills during this session.

35. My Government propose to take appropriate steps for the convening of a joint session of Parliament for the consideration of the Dowry Prohibition Bill in regard to which the two Houses have differed in some respects.

36. My Government will place before you the following Bills, among others, for your consideration:—

1. The Income-Tax (Amendment) Bill.
2. The Extradition Bill.
3. The Indian Patents and Design Bill.
4. The Essential Commodities (Amendment) Bill.
5. The Sugar Export Promotion (Amendment) Bill.
6. The Narcotics Bill.
7. The Apprenticeship Training Bill.
8. The Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms (Amendment) Bill.

37. Members of Parliament, I have drawn your attention to some of the main events and achievements, for the past year. I have also projected before you my Government's programme for the coming year. I have drawn your attention to the great tasks and burdens that are in front of us all. I have no doubt that these will engage your dedicated attention. Your understanding, vigilance and

[The President.]

co-operation in respect of the many problems of our economic planning, our defence, world peace and the struggle of still dependent peoples, will, I feel sure, be available to my Government and help to reassure our people. The resources of our country and the qualities of our people, stand engaged in the historic and tremendous tasks of national reconstruction and progress that are part of our destiny.

38. My Government will constantly endeavour to initiate and promote efforts and schemes to shorten the time between their decisions on policies and the implementation thereof. They will seek to enable our democracy to share and participate at all levels in the great economic and social developments that must progress, if we are to survive as an independent nation with dignity and a sense of fruitful function. The unity and the social well being of our entire people, the rapid progress to a democratic and socialist society, wherein changes must be timely and progress grow from more to more, must be attained peacefully and by consent.

39. Members of Parliament, I now bid you to your arduous labours and wish you success in them. I am confident that wisdom and tolerance and the spirit of co-operative endeavour will be your guide. May your labours yield a rich harvest and thus advance our country and people and the world which we are all pledged to serve.

12.16¾ hrs.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following eleven Bills passed by the Houses of Parliament during the last session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 5th December, 1960:—

(1) The Appropriation (Railways No. 5 Bill, 1960.

(2) The Appropriation (No. 5) Bill, 1960.

(3) The Indian Post Office (Amendment) Bill, 1960.

(4) The Tripura Excise Law (Repeal) Bill, 1960.

(5) The Railway Passenger Fares (Amendment) Bill, 1960.

(6) The Indian Tariff (Amendment) Bill, 1960.

(7) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1960.

(8) The British Statutes (Application to India) Repeal Bill, 1960.

(9) The Repealing and Amending Bill, 1960.

(10) The Prevention of Cruelty to Animals Bill, 1960.

(11) The Children Bill, 1960.

Sir, I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary of Rajya Sabha, of the following elevn Bills passed by the Houses of Parliament during the last session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 5th December, 1960:—

(1) The Employees' Provident Fund (Amendment) Bill, 1960.

(2) The Bilaspur Commercial poration (Repeal) Bill, 1960.

(3) The Mahendra Partap Singh Estates (Repeal) Bill, 1960.

(4) The Motor Vehicles (Second Amendment) Bill, 1960.

(5) The Preventive Detention (Continuance) Bill, 1960

(6) The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill, 1960.

(7) The Preference Shares (Regulation of Dividends) Bill, 1960.

(8) The Acquired Territories (Merger) Bill, 1960.